

The Institute
for Regional
Security

इंडो-पेसफिकि में शांति और समृद्धि की स्थापना

अनुसंधान नरिदेश

संस्थान के वर्तमान अनुसंधान और संवाद कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह पेपर डिजाइन किया गया है।

इसका उद्देश्य संस्थान इंडो-पेसिफिक सुरक्षा के लोगों के लिए सुरक्षा पर शोध करने वाले अन्य थकी टैक और टपिपणीकारों के काम को पूरा करे, जो एक परस्पर जुड़ी और बहुआयामी चुनौती है और इसमें सैन्य, मानव, आर्थिक और पर्यावरण सुरक्षा शामिल है।

इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि इंडो-पेसिफिक के लिए संस्थान की प्राथमिकताएं अन्य संस्थानों और उन चुनौतियों और प्राथमिकताओं से नपिटने वाले नीति शोधकर्ताओं को स्पष्ट हो जिनके साथ संस्थान सार्थक सहयोग कर सकता है।

क्रिसि गार्डनर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कैनबरा

जून 2023

इंडो-पेसफिकि में शांति और समृद्धि की स्थापना

1. इंडो-पेसफिकि में शांति और समृद्धि की स्थापना

ताइवान पर चीन सरकार के अधिकार और शासन के विस्तार को लेकर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) और ताइवान सरकार के बीच विवाद के कारण इंडो-पेसफिकि में शांति और समृद्धि को खतरा है। खतरा यह है कि संयुक्त राज् य अमेरिका और जापान सहित अन्य राज् य, दोनों के बीच किसी भी युद्ध में शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए ऐसे युद्ध की योजना और तैयारी की आवश्यकता है।

द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अधिकांश क्षेत्रीय राज् यों के चीनी गणराज् य (ROC) की सरकार के साथ संबंध थे। गृहयुद्ध के परिणामस्वरूप, जब 1949 में उस सरकार को सेना द्वारा ताइवान में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया गया था, तो उनमें से कई राज् यों ने 'वन चाइना' नीति अपनाते हुए और ताइवान पर PRC की संप्रभुता के दावे को स्वीकार करते हुए स्थिति ले ली और जारी रखी। ताइवान की सरकार और लोगों को जब PRC शासन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कुछ राज् यों ने द्वीप पर कब्जा करने के लिए PRC द्वारा सैन्य बल के किसी भी उपयोग में ताइवान का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने की इच्छा या अपनी मजबूरी का संकेत दिया है।

क्षेत्र के राज् यों को ताइवान सरकार को स्पष्ट रूप से संकेत देना चाहिए कि वे स्वतंत्रता की घोषणा का समर्थन या नفي नहीं करेंगे और सैन्य सहायता प्रदान नहीं करेंगे जहां चीन ने अपनी संप्रभुता को सैन्य रूप से लागू करके ऐसी घोषणा का जवाब दिया है।

हालाँकि, क्षेत्र के राज् यों को अपने व्यवहार में PRC के साथ स्वतंत्रता की किसी भी घोषणा के बाहर PRC शासन के सैन्य अधिरोपण के जवाब में ताइवान सरकार के साथ ऐतिहासिक और सहायक संबंध रखने वाले कुछ राज् यों से सैन्य हस्तक्षेप के महत्वपूर्ण जोखिम पर स्पष्ट रूप से जोर देना चाहिए। क्षेत्रीय राज् यों को चीन से ताइवान को बलपूर्वक शामिल करने की पहल न करने और शांतिपूर्ण पुनर् एकीकरण के लिए ताइवान सरकार के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि मांगनी चाहिए।

सभी पक्षों को चीन और ताइवान के बीच संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के साथ असंगत ताइवान और उसके आसपास सैन्य गतिविधियों से बचना चाहिए।

2. सीमा और क्षेत्रीय विवादों का गैर-सैन्य समाधान जसिमें विवादित क्षेत्र का गैर-सैन्यीकरण, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का उपयोग और ऐसे क्षेत्र के लिए संयुक्त विकास ढांचे पर बातचीत।

सीमा और क्षेत्रीय विवादों में शामिल दावेदारों की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई से इंडो-पेसफिकि में शांति और समृद्धि को खतरा है।

प्रदेश में क्षेत्रीय विवादों की सूची लंबी है और विवादों का इतिहास और दावे विवादित और जटिल हैं। पूर्व में इनमें कुरील द्वीप समूह, सेनकाऊ/डियाओयू द्वीप, डोकडो/ताकेशिमा द्वीप, स्पू रैटली द्वीप, पारासेल द्वीप समूह और दक्षिण चीन सागर का अधिकांश भाग शामिल हैं, जिसे चीन के दावों के अनुसार 'नाइन-डैश लाइन' के रूप में जाना जाता है। पश्चिम में इनमें तिब्बती-अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में चीन और भारत के बीच और पश्चिम में अक्सई चिन के साथ-साथ भारत-चीन सीमा पर भूटान और चीन

के बीच डोकलाम और भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच लद्दाख और लद्दाख और चीन के बीच सीमा विवाद शामिल हैं। हिंद महासागर में इनमें कई विवाद शामिल हैं, जिनमें फ्रांस, मेडागास्कर और कोमोरोस के बीच कई द्वीपों को लेकर और यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस के बीच चागोस द्वीपसमूह पर डिएगो गार्सिया में महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे को लेकर विवाद शामिल हैं।

कम से कम तीन विवादों में - एक जापान और रूस के बीच कुरील द्वीप समूह को लेकर, दूसरा जापान और चीन के बीच डियाओयू/सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर, और तीसरा चीन और फिलीपींस के बीच स्प्रेटली द्वीप समूह और समुद्र में और सामान्य रूप से उथल-पुथल को लेकर। दक्षिण चीन सागर पर चीन की संप्रभुता के दावे पर विवाद, संयुक्त राज्य अमेरिका को या तो एक दावेदार के साथ औपचारिक रक्षा गठबंधन के माध्यम से या समुद्र के कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधिसमझौता (UNCLOS) के तहत समुद्री मार्ग अधिकारों के दावे के माध्यम से विवाद में शामिल किया गया है।

ऐसे सभी विवादों में सम्मानित किए जाने वाले सदिधांत शामिल राज्यों के अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समानता और दावों का शांतिपूर्ण समाधान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी विवाद में मजबूत पक्ष वह सब करता है जो वह कर सकता है, जिसमें सैन्य रूप से बनाए गए 'जमीन पर तथ्य' या हथियारों के बल पर स्थापित 'नई क्षेत्रीय वास्तविकताएं' शामिल हों, और कमजोर पक्ष इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर हो। जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच है विवादित क्षेत्र में संसाधनों का साझा आर्थिक विकास अक्सर एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, इसे दावों की अंतर-राज्य बातचीत को नियंत्रित करने वाले तीसरे सदिधांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय राज्यों को नमिलखित के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए:

- ऊपर उल्लिखित तीन सदिधांतों के प्रति प्रतिबद्धता: समानता, शांतिपूर्ण समाधान और संयुक्त आर्थिक विकास।
- संभावित समझौते वाले विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए स्थानीय राष्ट्रीय समर्थन बनाने के लिए इन सदिधांतों को घरेलू स्तर पर बढ़ावा देना।
- सीमाओं पर विसैन्यीकृत क्षेत्रों और गैर-सैन्य प्रशासन और क्षेत्रों में उपस्थितिके लिए प्रतिबद्ध होना।
- ऐसे मामले के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का उपयोग जिसे इन्फ्रालेजिम या द्वारा नरिधारित करने की आवश्यकता है, या तीसरे पक्ष के समझौते में जहां मामले को पूर्व असमान और निःशुल्क नरिधारित करने की संभावना हो।

चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की महान शक्तियों के आसपास बहुध्रुवीयता वाले भविष्य में, क्षेत्र के राज्यों को क्षेत्रीय विवादों के प्रबंधन और समाधान पर केंद्रित इन प्रमुख शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय रणनीतिक वार्ता की स्थापना का समर्थन करना चाहिए।

3. दक्षिण चीन सागर के लिए एक प्रभावी 'आचार संहिता' पर बातचीत के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (ASEAN) के प्रयासों का समर्थन।

इंडो-पेसिफिक में शांति और समृद्धि को विवादित सीमाओं और विवादित क्षेत्र में झड़पों की वृद्धि को प्रबंधित करने के लिए सहमत आचार संहिता, जुड़ाव के नियमों और सहमत तंत्र की कमी से खतरा है।

जब तक क्षेत्रीय दावों और विवादों का समाधान क्षेत्र के सभी लोगों के हित में नहीं हो जाता, तब तक विवादकर्ताओं को सैन्य इकाइयों द्वारा अनजाने में की गई कार्रवाई या सामान्य संघर्ष में बढ़ने के जोखिम को कम करना चाहिए।

ASEAN वर्तमान में दक्षिण चीन सागर के लिए 'आचार संहिता' स्थापित करने के लिए चीन के साथ बातचीत में लगा हुआ है। इस प्रक्रिया और ASEAN के नेतृत्व को 2024 में ऐसे किसी भी कोड को औपचारिक रूप देने और लागू करने की दृष्टि से सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाना चाहिए।

ASEAN और चीन द्वारा सहमत आचरण की पछिली गैर-बाध्यकारी 2002 घोषणा, दुर्भाग्य से, समुद्र में 'नरिजन द्वीपों, चट्टानों, तटों, चट्टानों और किसी भी अन्य सुविधाओं' पर रहने के लिए कार्रवाई से बचने की प्रतिबद्धताओं के संबंध में अप्रभावी साबित हुई है।

क्षेत्रीय राज्यों को एक लागू करने योग्य कोड स्थापित करने के ASEAN के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए जो बहुपक्षीय बातचीत और समझौते पर UNCLOS प्रावधानों के साथ पूरी तरह से संरेखित हैं। इस तरह की प्रक्रिया को स्वीकार करने और उससे बंधे रहने और एक कोड को लागू करने की चीन की इच्छा पर क्षेत्रीय राज्यों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी ताकि क्षेत्र में एक महान शक्त के रूप में उसके चरित्र और व्यवहार का आकलन किया जा सके और यह निर्धारित किया जा सके कि इससे निपटने में कूटनीति और शक्ति पर भरोसा किया जाए या नहीं।

4. हथियारों के परसिंचरण के प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय रूपरेखा

इंडो-पेसिफिक में शांति और समृद्धि को पूरे क्षेत्र में या क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हथियारों की होड़ से खतरा है, जिसमें सैन्य व्यय में वृद्धि और हथियारों की पहुंच, शक्ति और परीष्कार दोनों शामिल हैं।

क्षेत्र में सैन्य व्यय में वृद्धि के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक:

- क्षेत्र में राज्यों द्वारा अनुभव किए गए आर्थिक विकास और वृद्धि से उन्हें अपनी रक्षा क्षमताओं में निवेश बढ़ाने के अवसर;
- सैन्य निवेश के साथ चीन का एक महान शक्ति के रूप में उभरना अन्य सभी क्षेत्रीय राज्यों (संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर) को बौना बनाना); और
- सैन्य झड़पों और क्षेत्रीय विवादों में वृद्धि और 'ग्रे ज़ोन' की घटनाओं को जो भी राज्य शामिल हो, समान रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता।

इस क्षेत्र में आगे परमाणु प्रसार का अस्तित्व वगत खतरा है। परमाणु हथियारों के संभावित प्राप्ति के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक हैं:

- उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल वितरण प्रणालियों का विकास, और अपने पड़ोसियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ उनका उपयोग करने की धमकी;
- चीन द्वारा अपनी परमाणु क्षमताओं का निरंतर विस्तार, भारत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षमताओं से मेल खाने की कोशिश करना और किसी भी परमाणु आदान-प्रदान में प्रतिस्पर्धा करना, और इसके और अन्य प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच हथियार संधियों की कमी; और

- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की गई 'वसिस्तारित परमाणु नरोध' की संभावित हानि और यदि संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र में प्रतिकारी शक्ति प्रदान करने में अनिच्छुक या असमर्थ है तो स्वतंत्र नरोध की कथित आवश्यकता।

अंततः स्वायत्त हथियारों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वैश्विक स्तर पर एक वैज्ञानिक और तकनीकी दौड़ चल रही है, जो निर्णय लेने में नित्य और भविष्य में सशस्त्र संघर्ष में वृद्धि के प्रबंधन के लिए मानव क्षमता से संबंधित मुद्दों को उठा रही है।

कूटनीतिक प्रयास नम्रानुसार किये जाने चाहिए:

- चीन द्वारा उत्तर कोरिया को परमाणु नरोध स्वीकरण के लिए मनाने और यदि आवश्यक हो तो उस पर दबाव बनाने के प्रयास, जिसमें यह दोहराना भी शामिल है कि चीन की वसिस्तारित नरोध उत्तर कोरिया की परमाणु हथियारों से लैस होने की आवश्यकता को समाप्त कर देती है और चीन द्वारा उस देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का पूर्ण समर्थन करना जहां वह परमाणु नरोध स्वीकरण नहीं करता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने सहयोगियों को अपनी निरंतर और प्रभावी वसिस्तारित नरोध प्रतिक्रियाओं के बारे में आश्वासन देने के प्रयास जारी रखना।
- क्षेत्रीय राज्यों द्वारा रक्षा व्यय के आसपास पारदर्शिता और विश्वास निर्माण के लिए - ASEAN नेतृत्व के तहत या एशिया में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों का सम्मेलन (CICA) जैसी पहल के तहत एक रूपरेखा और संवाद प्रक्रियाएं स्थापित करने के प्रयास; सैन्य क्षमताएं और संधि, बल मुद्दे, सगाई के नियम; और एआई और स्वायत्त प्रणालियों से जुड़ी उन्नत प्रौद्योगिकियां।

5. मानव, आर्थिक और पर्यावरण को संबोधित करने के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB), एशियाई विकास बैंक (ADB), क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) और हृदि-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF) जैसे संस्थानों और क्षेत्रीय आर्थिक वास्तुकला के भीतर सहयोग और समन्वय बढ़ाना खाद्य और जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन सहित आर्थिक और पर्यावरणीय सुरक्षा।

इंडो-पैसिफिक में शांति और समृद्धि को निरंतर गरीबी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे आर्थिक विकास की कमी और भोजन और पानी की असुरक्षा से खतरा है, जो जलवायु परिवर्तन और व्यापक सामाजिक अस्थिरता और असुरक्षा के कारण और भी गंभीर हो सकता है।

इंडो-पैसिफिक में करोड़ों लोगों के पास जीवन की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है या आर्थिक सुरक्षा का अभाव है जो उन्हें भोजन, आश्रय, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, अपराधियों से सुरक्षा जैसी बुनियादी चीजों तक पहुंच प्रदान करती है।

मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए साझा दायित्वों के संदर्भ में ऐसी आर्थिक असुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए लेकिन यह पूरे क्षेत्र में सामाजिक एकजुटता को नष्ट कर देती है। यह उग्रवाद के विकास और समुदायों के भीतर लोकलुभावन और सत्तावादी राजनीतिक नेताओं की ओर झुकाव का एक प्रमुख कारक है।

राज्य ऐसी गरीबी और असुरक्षा का सामना कर रहे नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वैध रूप से कार्य करते हैं। आर्थिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का एक कारक है और उदाहरण के लिए, दक्षिण चीन सागर में समुद्री संप्रभुता के लिए प्रतिस्पर्धा के अंतरनिहित कारकों में से एक है।

क्षेत्र में आर्थिक विकास और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय संस्थान और समझौते मौजूद हैं और क्षेत्र के राज्य संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य (SDG) के प्रति प्रतिबद्धता साझा करते हैं। क्षेत्र के राज्यों को:

- SDG प्रतिबद्धताओं के लिए आवश्यक संसाधन आवंटन को मजबूत करने के लिए इन संस्थानों और समझौतों के एजेंडे की समीक्षा करने के लिए कार्य करना चाहिए; और
- विकास देशों के मामले में, आपसी शांति और समृद्धि को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक साधन के रूप में क्षेत्र में विकास सहायता को बनाए रखने और बढ़ाने के मामले को घरेलू स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए।

6. सहयोगात्मक प्रयास जसिमें मानव तस्करी, जबरन यौन दासता और यौन शोषण, अवैध असूचित और अनियमति मछली पकड़ने सहित प्राकृतिक संसाधनों के शोषण, अवैध वन्य जीवन और पौधों का व्यापार और मादक पदार्थों की तस्करी में अंतरराष्ट्रीय अपराधों को संबोधित करने के लिए प्रवर्तन और मंजूरी प्रोटोकॉल और संचालन।

इंडो-पेसिफिक में शांति और समृद्धि को आपराधिक गतिविधियों में शामिल आपराधिक संगठनों और राज्यों द्वारा खतरा है, जो मानव, आर्थिक और पर्यावरणीय सुरक्षा को नष्ट कर रहे हैं।

एक बहु-डोमेन उदाहरण के रूप में खाद्य सुरक्षा और प्रोटीन तक पहुंच अब इस क्षेत्र में एक प्रमुख मुद्दा बन जाएगा। क्षेत्रीय राज्यों का एक समूह-प्रशांत द्वीप राज्य, विशेष रूप से न केवल भोजन के लिए बल्कि राष्ट्रीय राजस्व के लिए भी अपने आर्थिक बहिष्करण क्षेत्रों के भीतर मछली पकड़ने के संसाधनों पर निर्भर हैं। वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा प्रबंधन में मत्स्य पालन का सतत दोहन भी एक अत्यावश्यक विचार है।

IUU गतिविधियों में लगे मछली पकड़ने वाले बेड़े कुछ देशों की संप्रभुता के साथ-साथ उनकी समृद्धि के लिए खतरा पैदा करते हैं और क्षेत्र में महासागरों और समुद्रों के पारस्परिक, न्यायसंगत और टिकाऊ प्रबंधन के लिए खतरा पैदा करते हैं।

क्षेत्रीय राज्यों को अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और अवैध रूप से अज्ञात और अनियमति (IUU) मछली पकड़ने, निर्माण, साझा खुफिया जानकारी को मजबूत करने, डोमेन जागरूकता, निषेध, मंजूरी कानून पर संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय योजना के तहत सहयोग, समझौते और परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए।

7. राज्यों की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली प्रौद्योगिकियों और नविशों पर व्यापार प्रतिबंधों की पहचान और सीमा पर समझौता।

इंडो-पैसिफिक में शांति और समृद्धि को व्यापार पर अनावश्यक बाधाओं और विशेष प्रौद्योगिकियों, संसाधनों या क्षेत्रों पर नविश और व्यापार प्रतिबंध लगाने के अंतर-राज्य संबंधों पर प्रभाव से खतरा है।

सभी राज्य अपनी अर्थव्यवस्थाओं या समाजों के उन हिस्सों में पहुंच और नियंत्रण को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं जिन्हें वे राष्ट्रीय सुरक्षा या संप्रभु रक्षा क्षमताओं के लिए प्रासंगिक मानते हैं। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) अनुच्छेद XXI इस अधिकार को मान्यता देता है।

क्षेत्र के लोगों के आर्थिक विकास के लिए मुक्त और खुला व्यापार महत्वपूर्ण रहा है और रहेगा। करोड़ों लोग अभी भी उन लाभों का इंतजार कर रहे हैं जो खुले वैश्विक बाजारों द्वारा संकषम आर्थिक विकास लाता है।

कई राज्यों में हाल के फैसलों ने समृद्धि के लिए स्वतंत्र और खुली क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार प्रणाली के प्रति प्रतिबंधिता और व्यापार और नविश पर प्रतिबंध लगाने या कुछ प्रौद्योगिकियों, नविशों और क्षेत्रों के लिए सहयोगियों तक व्यापार और नविश को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई के बीच तनाव को उजागर किया है। उन्नत प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सिस्टम और दोनों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सामग्री के क्षेत्र ऐसे निर्णयों के केंद्र में रहे हैं।

इस तरह के निर्णय स्पष्ट मानदंडों के विरुद्ध पारदर्शी रूप से किए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार पर्याप्त किए जाने चाहिए कि प्रतिबंध के क्षेत्रों की पहचान सामान्य व्यापार संबंधों को खतरे में न डाले या अर्थव्यवस्थाओं के व्यापक वधितन और समृद्धि-सीमिति आर्थिक ब्लॉकों के निर्माण में योगदान न दे।

8. संयुक्त महामारी अनुसंधान, योजना, अभ्यास और संचालन के लिए क्षेत्रीय रूपरेखा और संसाधन।

इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि को कोविड-19 महामारी से खतरा हुआ है और यह भविष्य की महामारियों के कारण खतरे में है।

कोविड-19 ने खुलासा किया कि सीमाओं के पार लोगों और उत्पादों और वायरस की आसान और तेज़ आवाजाही की दुनिया में लोग और उनकी सुरक्षा एक-दूसरे से कतिनी जुड़ी हुई है। लाखों लोगों की आर्थिक सुरक्षा पर कोविड-19 का आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है और रहेगा।

राज्यों को महामारी तैयारी नवाचारों के लिए गठबंधन (CEPI) जैसी पहलों और संस्थाओं के लिए अपना समर्थन बढ़ाना चाहिए। हालाँकि, राज्यों को महामारी के खिलाफ वैकसीन और जैविक जवाबी उपायों में नविश को तैयारियों, संकट प्रबंधन और संपूर्ण समाज की प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति में सहयोग के साथ जोड़ना चाहिए।

राज्यों को महामारी प्रतिक्रियाओं और पुनर्प्राप्तिके मॉडलिंग और अनुकरण में सहयोग का पता लगाना चाहिए, जैसे वे युद्ध की तैयारी और युद्ध में अंतर-संचालनीयता के लिए समय-समय पर प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भाग लेते हैं। इस तरह के जोखिम प्रत्याशा अभ्यास और प्रतिक्रिया क्षमताओं में वभागीय और राज्य दोनों सीमाओं में अंतर-एजेंसी सहयोग शामिल होना चाहिए और वर्षा स्तर पर स्वास्थ्य, अनुसंधान, खजाना, सीमा नियंत्रण, परिवहन, पुलिसिंग, रक्षा और सरकारी संचार निर्णय निर्माताओं को शामिल करना चाहिए।

9. संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) योजना, अभ्यास और संचालन के लिए क्षेत्रीय रूपरेखा और संसाधन।

इंडो-पेसिफिक में शांति और समृद्धि को मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं से खतरा है, जो अधिक आवृत्ति और परिणाम के रूप में सामने आती है क्योंकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन इस क्षेत्र को प्रभावित करता है।

संयुक्त सैन्य अभ्यास की मिसाल का उपयोग करने के लिए, जिसमें कई राज्य नविश करते हैं, राज्यों को प्रमुख मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी में योजना बनाने और अभ्यास करने में सहयोग बढ़ाना चाहिए। परसंपत्तियों, कमांड संरचनाओं, गतिशीलता और परिचालन दक्षिण-पूरुब देशों की अग्रिम पहचान की जानी चाहिए जो परसंपत्तियों और कर्मियों की त्वरित, प्रभावी और निरंतर तैनाती की सुविधा प्रदान करते हैं और ऐसे अग्रिम मॉडलिंग और योजना के आधार पर नियमिति अभ्यास किए जाने चाहिए।

ऐसी प्रतिक्रियाओं को प्रभावी बनाने के लिए और क्षेत्रीय विश्वास निर्माण के हिस से के रूप में राज्यों को संयुक्त HADR योजना, अभ्यास और प्रतिक्रिया और वास्तव में महामारी पैनलिंग और प्रतिक्रिया की देखरेख के लिए एक क्षेत्रीय समझौते या संधि और संधि संगठन पर विचार करना चाहिए।

10. पूरे क्षेत्र में नीति और निर्णय निर्माता संचार और समझ को नियमिति और मजबूत करने के लिए ट्रैक 1.5 कूटनीति में नविश।

पूरे क्षेत्र के राज्यों में वरिष्ठ नीति और निर्णय निर्माताओं के बीच नियमिति और गहरी सहभागिता और समझ से इंडो-पेसिफिक में शांति और समृद्धि को बढ़ाया जाएगा।

सरकारें अंतर-दृष्टि और विचार लाने और संचालन में नीति लागू करने के लिए अपने नीति निर्माताओं और विभागीय नेताओं पर निर्भर रहती हैं। वे नीति और निर्णय निर्माता इस बात के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि सरकार कैसे और क्या देखती और सोचती है और एक राज्य अन्य राज्यों के साथ कैसे जुड़ता है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

ट्रैक 1.5 कूटनीति- सरकार को सूचित करने और लागू करने में शामिल वरिष्ठ नीति और निर्णय निर्माताओं की सुविधा, संकटों को रोकने और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक समझ, रश्मि, विश्वास और संचार चैनल का निर्माण। वे नीति और निर्णय निर्माताओं को 'वैदेशी' सोच और दृष्टिकोण से अवगत करा सकते हैं जो ऐतिहासिक और स्थितिजन्य जागरूकता दोनों को बढ़ाते हैं। वे प्रस्तावों को अक्सर साझा करने और आलोचना करने की अनुमति दे सकते हैं जो सरकारी राजनीतिक नेताओं के लिए संभव नहीं है।

इस कथन में जो कुछ भी प्रस्तावित है, उसे सरकार के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अनुमोदन और संसाधन के लिए विचार करने से पहले विकसित किया जाना चाहिए और वरिष्ठ नीति और निर्णय निर्माताओं द्वारा स्थितिजन्य व्यावहारिकताओं को निर्धारित किया जाना चाहिए। राज्यों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को हिंद-पश्चात के सभी लोगों की शांति और समृद्धि हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए नियमिति, प्रारंभिक, मध्यस्थता और कार्यान्वयन ट्रैक 1.5 गतिविधियों के माध्यम से कूटनीतिको ट्रैक करने के लिए रणनीतिक योजना और समर्थन देना चाहिए।

प्रमुख शोध वषिय-वस्तु

1. क्षेत्र की तीन महान शक्तियाँ - चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका - इस क्षेत्र में अपने संबंधों की सर्वोत्तम संरचना और प्रबंधन कैसे कर सकते हैं?
2. रक्षा व्यय, हथियारों के प्रसार, सैन्य मुद्राओं और AI के सैन्य अनुप्रयोग में विकास से संबंधित पारदर्शिता और विश्वास निर्माण स्थापित करने के लिए कनि राजनयिक, शासन संरचनाओं और तंत्रों का उपयोग किया जा सकता है?
3. भारत-प्रशांत क्षेत्र में वर्तमान क्षेत्रीय विवादों को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने और हल करने के लिए विवाद समाधान के कौन से तंत्र और साझा संसाधन विकास के दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं?
4. नीतियाँ, रणनीतियाँ और कूटनीतिक प्रथाएँ पैसेफिक आइलैंड्स फोरम (PIF), दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (ASEAN), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), अंटार्कटिक संधि प्रणाली और क्षेत्र में बहुपक्षवाद को कैसे मजबूत कर सकती हैं?
5. पूरे क्षेत्र में आर्थिक, मानव और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए AIIB और ADB जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं को बेहतर संरचित, समन्वित और तर्कसंगत कैसे बनाया जा सकता है?
6. क्षेत्र में राज्यों के बीच अधिकतम मुक्त और खुला व्यापार सुनिश्चित करने के लिए सहमत सुरक्षा मानदंडों के वरिद्ध व्यापार प्रतबंधों को सीमित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण संसाधनों के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को बेहतर ढंग से कैसे प्रबंधित किया जा सकता है?
7. राज्य महामारी और क्षेत्र में HADR के लिए संयुक्त अनुसंधान, योजना, अभ्यास और संचालन की बेहतर योजना और संरचना कैसे कर सकते हैं?

The Institute for Regional Security

info@ifrs.org.au

लेवल 4

42 मैक्वेरी स्ट्रीट

बार्टन ACT 2600

पीओ बॉक्स 4060

कगिस्टन ACT 2604

regionalsecurity.org.au

